



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

सांघिक्य प्रकाशित

Published by Authority

भाग 3 बुधवार, सके 1934- जनवरी 23, 2013

Part 3 Wednesday Saka 1934 - January 23, 2013

भाग 6 (अ)

जिला बाड, पार्षदां एवं नगर अयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(मण्डला दीन प्रयाल सपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 27, 2012

संख्या एफ-6() आ.राज.(सा.प्र.)/जननि/2012/682- नगर निगम जयपुर की साधारण सभा मीटिंग दिनांक 13-06-2012 के प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां 2012 की स्वीकृति प्रदान की गई है, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनाार्थ उक्त उपविधियां प्रकाशित की जाती है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 संपठित धारा 339 (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर एतद्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां 2012 नगर निगम जयपुर की साधारण सभा में स्वीकृति दिनांक 13-06-2012 से प्रभावशील होगी।

नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां, 2012

नगर निगम जयपुर की साधारण सभा की मीटिंग दिनांक 13-06-12 के प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां, 2012 की स्वीकृति प्रदान की गई है, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनाार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नगर निगम जयपुर में विवाह स्थल से आमजन को होने वाली असुविधा एवं निकाय द्वारा सम्पादित सेवाओं पर बढ़ते हुए दबाव के कारण विवाह स्थलों के संचालन के नियंत्रण हेतु जनहित में उपविधि बनाया जाना आवश्यक हो गया है। नगर निगम जयपुर के न्यायालय जोधपुर द्वारा भी एकलपीठ दीवानी याचिका संख्या 7275/06 श्री राजकुमार ताया बनाम सरकार व अन्य में दि. 11-04-08 को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया था। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 339 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नगर निगम जयपुर द्वारा बनाये गये सलमन नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधित उपविधियां, 2012 स्वीकृत करती है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) की धारा 339 (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर एतद्वारा संशोधन उपविधियां बनाता है, प्रस्ताव :-

नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां, 2012

1. शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव :-

(क) ये उपविधियां नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां, 2012 कहलायेंगी।

(ख) ये उपविधियां नगर निगम जयपुर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 13-06-2012 की स्वीकृति दिनांक से प्रभावशील होगी।

(ग) ये उपविधियां नगर निगम जयपुर की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी।

2. शाब्दिक परिभाषाएं :- जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी :-

(i) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है।

(ii) समिति से तात्पर्य नगर निगम जयपुर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अंतर्गत गठित समिति से है।

(iii) स्थानीय निकाय से तात्पर्य नगर निगम जयपुर से है।

(iv) उपयोग व उपभोग अनुमति से तात्पर्य विवाह स्थल पर इन उपविधियों के अंतर्गत उपविधि 2 के खण्ड (ix) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से है।

(v) अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल पंजीयन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कृतव्यवस्था संबंधक सम्भिलित होगा।

(vi) "महापौर" से तात्पर्य नगर निगम जयपुर के महापौर से है।

... किन्तु ... प्रस्तुत करना ...

- (क) ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग में उपविधि संख्या 9 (d) की पालना की जावेगी।
- (ख) विवाह स्थल पर आवाजों की बाधाओं को रोकने के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार गार्ड लगाए जाने के संबंध में उपविधि सं. 11 की पालना की जावेगी।
- (ग) विवाह स्थल पर आवाजों से उत्पन्न कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थ निगम- अलग पोलिसिंग में पत्र जर्के नगर निगम जयपुर के सफाई कर्मचारियों को सुपूर्द करने के संबंध में उपविधि सं. 13 की पालना की जावेगी।
- (घ) उपविधियों द्वारा निर्धारित प्रति आयोजन सफाई शुल्क जमा कराने के संबंध में उपविधि सं. 12 की पालना की जावेगी।

समस्त वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् स्थानीय निकाय के अधिकृत प्राधिकारों अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा। नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक निगम तक लाईसंस देने की ऑनलाईन प्रक्रिया लागू कर सकेंगे। ऐसी दशा में आवेदक प्रार्थना पत्र के साथ सभी औपचारिक दस्तावेज एवं फीस अदायगी की रसीद प्रस्तुत करेंगे। फीस अदा होने के 30 दिवस में अनुज्ञप्ति अधिकारी/जोन आयुक्त/आयुक्त (राजस्व)/कायर ऑफिसर/राजस्व अधिकारी तक विवाह स्थल की जांच उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप करेगा तथा विवाह स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति देगा। अस्वीकृत होने की दशा में कारण बताओ नोटिस जारी कर आवेदक को सुनना और पुनः यथोचित आदेश जारी करेगा। निरस्त होने की दशा में जमा शुल्क लौटाया नहीं जावेगा। किंतु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता द्वारा चालू विस्तार वर्ष में स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया गया है तो 5000/- रु. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

- 5. प्रक्रिया- प्रक्रिया में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की बाध्यता विलोपित की जाती है।
- 6. भूमि/भवन स्वामित्व की जांच- यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दरतावेज संलग्न नहीं किये गये हों या वांछित दरतावेज जांच में सही नहीं पाये जायें तो उपविधि 4 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। किंतु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया है तो 5000/- रु. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेष राशि लौटा दी जावेगी। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।
- 7. अपील- विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी आपत्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में उल्लिखित नियम उपनियम समिति में की जा सकेगी।
- 8. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा- स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 9. प्रतिबंधित क्षेत्र-
 - (a) ऐसे स्थान पर जहाँ पर अस्पताल, शैक्षिक/शैक्षणिक संस्थाएँ या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा आती हो, वहाँ पर विवाह स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - (b) विवाह स्थल का संचालन विधि/स्थालय से 100 फीट की परिधी में प्रतिबंधित होगा।
 - (c) राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर स्थानीय निकाय सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सकती है।
 - (d) निर्धारित समय रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस बाबत विवाह स्थल पर इस संबंध में बोर्ड लगाना आनवाय होगा। जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि यंत्रों के संबंध में जारी निर्देशों/प्रतिबंधों को पूर्ण पालना करनी होगी।
- 10. अग्निशामक के आपत्ति प्रमाण पत्र का शुल्क निम्नानुसार वसूल किया जावेगा-
 - (i) 1500 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल के लिए - 1000 रु. वार्षिक
 - (ii) 1500 से अधिक 5000 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल के लिए - 2000 रु. वार्षिक
 - (iii) 5000 वर्ग मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए - 3000 रु. वार्षिक
- 11. प्रत्येक विवाह स्थल पर विवाह या अन्य आयोजन के दिन विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्च पर विवाह स्थल के बाहर निम्नानुसार गार्डों की व्यवस्था करनी होगी-

- (ii) 1500 वर्ग मी. से कम के विवाह स्थल के लिए - 2 गांठ
 (iii) 1500 से 5000 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल के लिए - 3 गांठ
 (iii) 5000 वर्ग मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए - 4 गांठ

ये गांठ वाहनों को विवाह स्थल की निर्धारित क्षमता के विवाह स्थल पर ही खड़ा करके विवाह स्थल के सामने यातायात को बाधित होने से रोकेगा।

12. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारियों से निम्नानुसार सफाई शुल्क वसूल किया जावेगा :-

- (i) 1500 वर्ग मी. से कम के विवाह स्थल के लिए - 10,000 रु. प्रति वर्ष
 (ii) 1500 से 5000 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल के लिए - 20,000 रु. प्रति वर्ष
 (iii) 5000 वर्ग मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए - 30,000 रु. प्रति वर्ष

उक्त सफाई शुल्क वर्ष में दो किस्तों में जमा होगा प्रथम किस्त अप्रैल में एवं द्वितीय किस्त अक्टूबर में देनी होगी। यदि कोई विवाह स्थल मालिक/संचालक पूरे वर्ष का शुल्क अक्टूबर में जमा कराता है तो उसे 10 प्रतिशत छूट दी जावेगी।

13. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थों को अलग-अलग पॉलीथिन बैग में पैक करवाकर निगम के सफाई कर्मचारियों को सुपुर्द करना होगा। विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को अपशिष्ट पदार्थों को निगम के कचरा डिपो के पास विवाह स्थल के आसपास या बाहर फेंकना नहीं डालेगा यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने पर जुर्माना वसूल किया जावेगा।

14. विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजीयन एवं अनुमति शुल्क:-

(अ) इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पर प्रति वर्ष क्षेत्रफल के अनुसार पंजीयन शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा:-

- (a) 1000 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल 10,000/- रु. वार्षिक
 (b) 1000 वर्ग मी. से अधिक 1500 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल 20,000/- रु. वार्षिक
 (c) 1500 वर्ग मी. से अधिक 2500 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल 30,000/- रु. वार्षिक
 (d) 2500 वर्ग मी. से अधिक 5000 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल 50,000/- रु. वार्षिक
 (e) 5000 वर्ग मी. से अधिक के विवाह स्थल 60,000/- रु. वार्षिक।

नोट:- उपरोक्त शुल्क वार्षिक ना होकर एकमुश्त होगा किन्तु प्रतिवर्ष पंजीयन का नवीनीकरण किया जावेगा जोकि बिन्दु सं. 14 के (ब) विवाह स्थल के उपयोग का अनुमति प्राप्त प्रतिवर्ष जमा कराने के उपरान्त किया जावेगा।

(ब) विवाह स्थल उपयोग का अनुमति शुल्क 10/- रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष देय होगा।

(स) उपरोक्त (अ) व (ब) शुल्क वित्तीय वर्ष के अनुसार देय होंगे यदि विवाह स्थल वित्तीय वर्ष के मध्य में स्थापित किया जाता है तो भी पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

उपरोक्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क एवं विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) शुल्क, नगरीय निकाय को देय किसी भी अन्य शुल्क कर इत्यादि के अतिरिक्त होगा।

नोट: किन्तु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में शुल्क का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया है तो 5000/- रु. प्रोसेसिंग शुल्क जमा में शेष राशि लौटा दी जावेगी।

15. नगर निगम जयपुर को उपरोक्त सभी धरों में प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् शुल्क वृद्धि करने का अधिकार होगा।

16. नवीनीकरण:- अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात् विवाह स्थल पंजीयन का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा जिसके लिये अनुमति प्राप्तकर्ता को पूर्ण वृत्तियों के साथ आवेदन करना होगा, परन्तु-

(क) विलोपित की जाती है।

(ख) विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति शुल्क पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होना यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ग) 01 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थल के लिए अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो प्रत्येक तीन माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शारिर्त एवं तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष के विलम्ब पर 100/- रु. विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क शारिर्त को जमा करना होगा।

17. विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) का अनुमति पत्र निम्न शर्तों के अधीन होगा :-

(क) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के चारों ओर सुरक्षा सखधी आवश्यक प्रदान किया जावेगा।

- अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी शर्तें परिसर के बाहर 6 X 4 फीट के अतिरिक्त अधिक की ऊंचाई तक अग्निशमन स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।
- (अ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी शर्तें/निर्देशों का पालना करना होगा।
- (ब) विवाह स्थल अनुमतिपत्रधारियों को कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थों को अलग-अलग प्लास्टिक में पैक करवाकर निगम के सफाई कर्मचारियों को सुपूर्द करना होगा। विवाह स्थल अनुमतिपत्रधारियों को कचरा व अपशिष्ट पदार्थों को निगम के कचरा डिपो के पास, विवाह स्थल के अलग-पान रा बाहर नदक पर नहीं डालेंगे यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जायेगा।
- (क) यह अपने विवाह स्थल पर अग्निशमन से संबंधित निर्धारित उपकरण लगवाया जाना सुनिश्चित करेगा। आइसर्स जारी होने के पश्चात् अग्निशमन अधिकारी विवाह स्थल परिसर को जांच कर सकेंगे एवं उक्त परिसर में अग्निशमन के मापदण्ड पूर्ण नहीं पाता है तो लाइसेंस निरस्त करने की अभिशाप लाइसेंस अथोरिटी को देगा।
- (ख) स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल से कचरा उठाने के लिए निर्धारित किया गया शुल्क अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।
- (ग) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के कुल क्षेत्र का 25 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वयं के खर्च पर उपलब्ध करवाना होगा एवं उस क्षेत्र को बैरिकेड्स आदि अलग-अलग पृथक से प्रकिसम प्रदर्शित करेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल से अनुमोदित ले-आउट स्थल में इतने शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (घ) गन्ध/राज्य सरकार के ध्वनि/वायु प्रदूषण एवं अन्य संबंधी नियमों/अभिनियमों की पालना अनुमतिपत्रधारियों द्वारा की जायेगी।
18. अभियोजन:- नगर निगम जयपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कनिष्ठ पद का नहीं होगा विवाह स्थल का निरीक्षण कर सकेंगे। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तों उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 3 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित किया जायेगा, यदि नियत अवधि में अनुमति प्राप्तकर्ता पालना नहीं करता है तो अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल सम्पत्ति को सीज किया जाकर दीर्घ व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरुद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने को कार्यवाही प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।
19. समझौता:- न्यायालय में विचारधौन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित सनिति या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत सनिति/अधिकारी को होगा।
20. उपविधियों का उल्लंघन:- इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10000/-रु. का अर्थदण्ड दिया जाकर उपविधि सं. 17 के अंतर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरुद्ध अन्त में लाई जायेगी।
21. अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवाना:- अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
22. अवैध विवाह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही:- यदि किसी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के स्थानीय निकाय क्षेत्र में विवाह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो कार्यवाही की जायेगी।
23. उपविधियों की किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर विवाह स्थल को सीज करने का अधिकार अनुमति अधिकारी को होगा एवं इसकी अपील 30 दिवस में महापौर महो. को की जा सकेगी। महापौर नगर निगम दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करेंगे।
24. जनरेटर रूम की व्यवस्था:- नगर निगम जयपुर क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों में जनरेटर सेट इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो।
25. सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोक:- स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छूटे गये हैं उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नहीं किया जायेगा, न ही उन्हें अनुमति पत्र जारी किया जायेगा। उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जा सकेगा।
26. सामुदायिक केन्द्रों में विवाह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूट:- भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है परन्तु ऐसे विवाह स्थल जिनका संचालन भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधि 14 में दर्शायी गयी दरों में छूट होगी।

27. पतिंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना-- अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विवाह स्थल के खर्च पर सुनिश्चित करने होगी। अर्थात् यह विवाह के आयोजन के लिए प्रयोग करने के लिए विवाह स्थल को जलपाव की सुविधाएं होनी चाहिए।
28. विवाह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंध-- अनुमति प्राप्त करने वाले विवाह स्थलों को अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की प्रतियों को संबंधित अधिकारियों को भेजना आवश्यक होगी। स्थानीय निकाय द्वारा समाज के सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए विवाह स्थल (उपयोग व उपयोग) को जारी अनुमति पत्र में प्रकाश की भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अधिकार नहीं मान्य तब तक अनुमति पत्रों द्वारा भविष्य में संबंधित स्थल का भू-उपयोग परिवर्तन चाहते पर राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत अपेक्षा पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित अधिकारियों अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।
29. स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षित-- विवाह स्थल (उपयोग एवं उपयोग) अनुमति पत्र भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल को जारी अनुमति पत्र की शर्तों का कठोर रगड़ दिए बिना निरस्त करने का अधिकार। निरस्तकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की शर्तों पर ध्यान नहीं देना।
30. वर्तमान में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों को विवाह स्थल अनुमति प्रमाण पत्र जारी करके संबंध में-- नगर निगम जयपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर निगम जयपुर के विवाह स्थलों में वर्तमान में संचालित विवाह स्थलों एवं उपस्थिति 2 के अन्तर्गत (IX) में वर्णित अन्य गतिविधियों का उपयोग में लाये जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण अभियुक्त जारी होने के 30 दिनों की अवधि में करवाया जाकर जोनवार सूची तैयार की जाकर उपरोक्त सख्त 14,16,17,18 एवं 19 के कार्यालयों की जावेगी।
31. अनुमति प्राप्तकर्ता से शपथ पत्र प्राप्त किया जाना-- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल को स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से 10 रु के नॉन-रिटर्न डिपॉजिट स्टांप पत्र पर शपथ का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित शर्तों देश निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपयोग को निरस्त रगड़ जा सकेगा।
32. निरसन और व्यावृत्तियों-- इन उपविधियों को प्रदान में अपने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/दिशानिर्देश निरस्त समझी जावेगी। लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में अपने को पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/दिशानिर्देशों के तहत दिया गया कोई कार्य उपविधियों प्रभावशील होने का कारण अवैध नहीं समझा जावेगा।

साधारण अना की आइटी।

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(षण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)
विवाह स्थल उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाक्य प्रार्थना पत्र
प्रपत्र-क

1. विवाह स्थल का नाम	
2. विवाह स्थल का पता	
3. आवेदक का नाम	
4. पता/दूरभाष नं. (कार्या/निवास/मोबाईल)	
5. भूखण्ड मालिक का नाम, पता व दूरभाष नं. (कार्या/निवास/मोबाईल)	
6. विवाह स्थल का कुल क्षेत्रफल	
7. अपेक्षित स्थल की कुल व्यक्तियों के समाहित करने की क्षमता	
8. अग्निशमन के अनुमति प्रमाण पत्र के जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति	
9. सफाई शुल्क जमा की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति	
10. पंजीयन जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति	
11. अनुमति जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति	

